# 06 February 2023: PIB Summary for UPSC

## 06 फरवरी 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:


1. प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में HAL हेलीकाप्टर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया:
2. मत्स्य पालन विभाग के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में गत वर्ष की तुलना में 38.45% की समग्र वृद्धि:
3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने एक्सटेंशन प्रणाली को सशक्त करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:
4. 'पीएम गतिशक्ति' की प्रगति की समीक्षा:
5. कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध 43 दिनों की तीर्थ यात्रा पर 1100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे:
6. युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया:
7. G-20 के तहत पर्यटन कार्यसमूह की पहली बैठक गुजरात के कच्छ के रण में शुरू होगी:


### 1. प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में HAL हेलीकाप्टर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया:

सामान्य अध्ययन: 3

आर्थिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्रारंभिक परीक्षा: पीएम गतिशक्ति, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर (IMRH)।

मुख्य परीक्षा: देश की रक्षा एवं विकास में HAL हेलीकाप्टर संयंत्र की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

**प्रसंग:**

- प्रधानमंत्री ने 06 फरवरी को तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप और तुमकुरु में तिप्टूर और चिक्कानायकनहल्ली में दो जल जीवन

मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर संयंत्र और संरचना हैंगर का दौरा किया और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण किया।

**उद्देश्य:**

- यह सुविधा भारत को हेलीकॉप्टरों की अपनी संपूर्ण आवश्यकता को स्वदेशी रूप से पूरा करने में सक्षम बनाएगी और भारत में हेलीकॉप्टर डिजाइन, विकास और निर्माण में आत्मनिर्भरता का गौरव प्राप्त करेगी।

**विवरण:**

- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की।
    - इसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी।
    - यह एक समर्पित नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इकोसिस्टम को आगे बढ़ाएगी।
    - यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का उत्पादन करेगी।
    - LUH एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3-टन वर्ग, एकल इंजन बहुउद्देश्यीय उपयोगिता हेलीकाप्टर है, जिसमें उच्च गतिशीलता की अनूठी विशेषता है।
    - कारखाने का विस्तार अन्य हेलीकॉप्टरों जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर (IMRH) के निर्माण के साथ-साथ भविष्य में LCH, LUH, सिविल ALH और IMRH की मरम्मत और ओवरहाल के लिए किया जाएगा।
    - कारखाने में भविष्य में सिविल LUH के निर्यात की भी संभावना है। कारखाने में उद्योग 4.0 मानकों का विनिर्माण सेट-अप होगा।
    - अगले 20 वर्षों में, HAL तुमकुरु से 3-15 टन के वर्ग में 1000 से अधिक हेलीकाप्टरों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है।
    - इससे प्रदेश में करीब छह हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
- प्रधानमंत्री ने तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखी।

- राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत, तुमकुरु में तीन चरणों में 8484 एकड़ में फैले औद्योगिक टाउनशिप का विकास चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया गया है।
- कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने तुमकुरु में तिपतुर और चिक्कनायकनहल्ली में दो जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
  - तिप्तूर बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई जाएगी।
  - लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से चिक्कानायकनहल्ली तालुक की 147 बस्तियों के लिए बहु-ग्राम जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा।
  - इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
- आज HAL भारत की सेना के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है।
- फूड पार्क और HAL के बाद औद्योगिक टाउनशिप तुमकुरु के लिए एक बड़ा उपहार है जो तुमकुरु को देश के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगा।
  - पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान के तहत टाउनशिप का विकास किया जा रहा है, जो मुंबई-चेन्नई राजमार्ग, बेंगलुरु हवाई अड्डे, तुमकुरु रेलवे स्टेशन, मंगलुरु बंदरगाह के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से जुड़ा होगा।

## 2. मत्स्य पालन विभाग के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में गत वर्ष की तुलना में 38.45% की समग्र वृद्धि:

**सामान्य अध्ययन: 3**

**कृषि:**

**विषय: पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।**

**प्रारंभिक परीक्षा: प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY), मत्स्य अवसंरचना विकास निधि (FIDF) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)।**

**प्रसंग:**

- **वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मत्स्यपालन विभाग के लिए 2022-23 के दौरान 1624.18 करोड़ रुपये और 2021-22 के दौरान 1360 करोड़ रुपये के मुकाबले 2248.77 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन की घोषणा की है।**

**उद्देश्य:**

- **यह वित्त वर्ष 2022-23 के बजट की तुलना में 38.45% की समग्र वृद्धि को दर्शाता है और यह विभाग के लिए अब तक के सबसे अधिक वार्षिक बजटीय सहयोग में से एक है।**

**विवरण:**

- **इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) नाम से एक नई उप-योजना की घोषणा की है:**
    - **PMMSY के तहत केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना जिसमें 6,000 करोड़ रुपये का लक्षित निवेश है, जिसका उद्देश्य मछुआरे, मछली विक्रेता और मत्स्य क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमी की आय को और बढ़ाना है।**
    - **PM-MKSSY ने मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप की परिकल्पना की है और इसमें डिजिटल समावेशन, पूंजी निवेश और कार्यशील पूंजी के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना, जलीय कृषि और मत्स्य पालन में जोखिम को कम करने के लिए प्रणाली और संस्थानों को प्रोत्साहन देना शामिल है।**
    - **मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र मूल्य-श्रृंखला दक्षताओं पर काम करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उपभोक्ताओं को सुरक्षित मछली उत्पादों के वितरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे घरेलू बाजार का विस्तार होता है और इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरियों के सृजन और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन मिलता है।**
- **बजट भाषण में पंचायत स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियों सहित प्राथमिक सहकारी समितियों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है।**

- जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों का गठन इस क्षेत्र को औपचारिक रूप देगा और मछली उत्पादन एवं इसके बाद की गतिविधियों को संगठित तरीके से करने के लिए मछुआरों और मछली किसानों को सशक्त करेगा।
    - सहकारी समितियों के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय के लिए ९०० करोड़ रुपये का आवंटन, ऋण की बढ़ी हुई सीमा इस क्षेत्र में सहकारी समितियों के संचालन और वित्तपोषण को आसान बनाने की उम्मीद है और क्षेत्र को तेजी से बढ़ने में मदद करेगा।
    - उपर्युक्त, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय सहकारी समिति और राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य बीज सहकारी समिति की स्थापना पर पहले की घोषणा के अलावा, बीज और विपणन के क्षेत्रों में मत्स्य पालन का सहयोग करने की उम्मीद है।

- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की गई है।
    - इससे मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संस्थागत वित्त के प्रवाह में काफी सुधार होगा।
    - फिश मील पर बुनियादी सीमा शुल्क में 15% से 5%, क्रिल मील पर 15% से 5%, एल्गल प्राइम (आटा) पर 30% से 15%, फिश लिपिड ऑयल पर 30% से घटाकर 15% और आगे जलीय फ़ीड के निर्माण के लिए खनिज और विटामिन प्रीमिक्स 15% से 5% तक फीड की लागत कम करने, घरेलू फीड को बढ़ावा देने और भारतीय श्रिंप के निर्यात प्रतिस्पर्धी में काफी सुधार करने की उम्मीद है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भारत में 3 उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की घोषणा से भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यह मछली विपणन प्रणालियों में सुधार के लिए और ट्रैसेबिलिटी और गुणवत्ता के लिए ब्लॉक-चेन आधारित समाधान के त्वरित कार्यान्वयन के माध्यम से मूल्य वृद्धि के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान करता है।
- प्रस्तावित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और कृषि त्वरक कोष मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला से संबंधित नवाचारों को तेज करेगा।

- ○ कुल मिलाकर, बजट 2023-24 संस्थागत ऋण के बढ़ते प्रवाह, जोखिम कम करने के लिए बढ़े हुए साधनों, घरेलू और निर्यात बाजारों के विस्तार और गहनता के लिए प्रोत्साहन और तेजी के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के एक नए चरण की शुरुआत करने में मदद करेगा।
- ○ **भारत पहले ही तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक और मछली और मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।**
- ○ इसने वित्त वर्ष 2021-22 में 10.34% की दो अंकों की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है और निकट भविष्य में और अधिक वृद्धि के साथ 162.48 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन तक पहुंच गया है।
- ○ यह क्षेत्र 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है जो ज्यादातर हाशिए पर और कमजोर समुदायों के भीतर हैं और गरीबों और दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में स्थायी सुधार लाने में सहायक रहे हैं।

- चार साल पहले, 5 फरवरी 2019 को तत्कालीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग से **मत्स्य विभाग** को अलग करके मत्स्य क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा दिया गया था।
  - ○ इसके साथ ही, 27500 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ कई दूरदर्शी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY), मत्स्य अवसंरचना विकास निधि (FIDF) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लॉन्च किया गया था, जिसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है।

**3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने एक्सटेंशन प्रणाली को सशक्त करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:**

**सामान्य अध्ययन: 3**

**कृषि:**

**विषय: किसानो की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।**

**प्रारंभिक परीक्षा: डिजिटल ग्रीन, डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म ।**

**मुख्य परीक्षा: इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के किसानों पर होने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।**

**प्रसंग:**

- भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के एक डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत नई दिल्ली में डिजिटल ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**उद्देश्य:**

- यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड बहु-प्रारूप बहु-भाषी सामग्री की एक डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराएगा।
- परिकल्पित प्लेटफॉर्म भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक मंच के रूप में उभरने के लिए राष्ट्रीय प्रणालियों में योगदान देगा और सहायक के तौर पर कार्यान्वित होगा।
- यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जो एक्सटेंशन वर्कर्स को क्यूरेट की गई सामग्री को समय पर किसानों तक पहुंचाने तथा वितरित करने में मदद करेगा।
- इसके अलावा, यह प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक्सटेंशन वर्कर्स के विशाल नेटवर्क का कौशल विकास करने में सहायता प्रदान करेगा।

**विवरण:**

- प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा बनाए जा रहे डिजिटल कृषि इकोसिस्टम की मजबूत नींव ही किसानों को जोड़कर विस्तार प्रणाली को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
    - इस एक्सटेंशन प्रणाली की डिजिटल क्षमता किसानों को डिजिटल कृषि का लाभ उठाने में सहायता करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है और यह हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में काम करेगी।
- भारत में कृषि, आजीविका और संबद्ध क्षेत्रों में 200,000 से अधिक एक्सटेंशन वर्कर्स हैं।
    - यह महत्वाकांक्षी पहल कृषि, बागवानी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका विभागों के आउटरीच कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत सामग्री निर्माण तथा लक्षित प्रसार के माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत आगे ले जाने का रास्ता तय करेगी।

- यह प्लेटफॉर्म छह महीने के भीतर लॉन्च किया जाना है।
- इस प्लेटफॉर्म में पोर्टल तथा देश भर के पूरे कृषक समुदाय की सेवा करने की क्षमता और नए एवं उच्च मूल्य प्रस्ताव के साथ एगटेक व अन्य बाजार अभिकर्ताओं को उत्प्रेरित करने की क्षमताएं होंगी।

- यह समझौता डिजिटल ग्रीन के साथ हस्ताक्षरित किया गया है, जो एक पुरस्कार विजेता सामाजिक उद्यम है।
  - यह छोटे व सीमांत किसानों को उनकी उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, उनकी एजेंसी को मजबूत करने और सामुदायिक स्तर के लचीलेपन का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठा रहा है।
  - डिजिटल ग्रीन, टेक्नोक्रेट और सामाजिक विकास के प्रति उत्साही रिकिन गांधी द्वारा स्थापित किया गया है।
  - यह बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है तथा 25 लाख से अधिक किसानों के लिए सेवारत है और इसने 4000 से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर्स की क्षमता में वृद्धि की है।

**प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:**

1. **'पीएम गतिशक्ति' की प्रगति की समीक्षा:**

- अक्टूबर 2021 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक पीएम गतिशक्ति संस्थागत रूपरेखा के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) ने पिछले एक साल में 41 बैठकें की हैं और पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुसार 61 परियोजनाओं का विश्लेषण किया है और उन पर गौर किया है।
  - ये सड़क, रेलवे, औद्योगिक गलियारों, प्राकृतिक गैस, बंदरगाहों और शहरी अवसंरचना से संबंधित थीं।
- समीक्षा में यह बताया गया कि विभिन्न मंत्रालय अब अभिनव तरीकों से 'पीएम गतिशक्ति एनएमपी' को अपना रहे हैं।
  - रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब 2000 से भी अधिक गुड्स शेड के लिए सड़क कनेक्टिविटी वाली परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं।

- इसी तरह कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे क्षेत्रों से संबंधित 156 महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतर (गैप) की भी पहचान की गई।
- अत्याधुनिक 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए दूरसंचार विभाग और राज्य सरकारें 5G सेल की स्थापना करने हेतु उपयुक्त स्ट्रीट फर्नीचर की पहचान करने के लिए एनएमपी का उपयोग कर रही हैं।

- सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
  - 14 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों को अब पीएम गतिशक्ति के तहत शामिल किया गया है जिनमें पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, खेल विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और आयुष मंत्रालय शामिल हैं।
- पीएम गतिशक्ति से जुड़े अपने अनुभवों, सर्वोत्तम तौर-तरीकों और दृष्टिकोण पर राज्यों के साथ संवाद करने के लिए आने वाले महीनों में 6 क्षेत्रों यानी उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
  - इन कार्यशालाओं में केंद्र एवं राज्य स्तरों पर अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चाएं की जाएंगी, लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई जाएंगी, इनका कार्यान्वयन और निगरानी की जाएगी, शहरी विकास के लिए शहर लॉजिस्टिक्स योजनाएं बनाई जाएंगी, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स में सुगमता (लीड्स) सर्वेक्षण, 2023 कराया जाएगा, और प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी।

2. **कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध 43 दिनों की तीर्थ यात्रा पर 1100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे:**

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की कि कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्री सांगवोल सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया द्वारा आयोजित पैदल यात्रा के हिस्से के रूप में 43 दिनों में 1,100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे।
    - इस अवसर का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया आपसी राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं।
    - तीर्थयात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना है।
    - पर्यटक भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे और बाद में नेपाल जाएंगे।
- प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार भारत में बौद्ध पर्यटन सर्किट को दुनिया भर में प्रचारित किया जाए।
    - इस सर्किट का उद्देश्य पर्यटकों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने में मदद करना और बुद्ध के जीवनकाल के दौरान उनके पदचिह्नों की खोज करना है।
    - तीर्थयात्रा के दौरान कवर किए जाने वाले स्थलों में बुद्ध के जन्म से लेकर उनके परिनिर्वाण तक का जीवन शामिल है।
- पर्यटक 9 फरवरी से 23 मार्च, 2023 तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों के 43 दिनों की यात्रा पर रहेंगे।
    - **'ओह, वी! ओह लव! ओह, लाइफ!'** के नारे के साथ सांगवोल सोसायटी द्वारा आयोजित तीर्थयात्रा का उद्देश्य भारत की तीर्थयात्रा के माध्यम से भक्ति संबंधी गतिविधियों की बौद्ध संस्कृति का प्रसार करना है, जहां बुद्ध का जीवन और पदचिह्न संरक्षित हैं।
- भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत श्री चांग जे-बोक ने कहा कि वर्ष 2023 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 50 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं।
    - यह अवसर भारत की G-20 की अध्यक्षता के साथ-साथ आया है और दक्षिण कोरिया G-20 में भारत की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है।

  - बौद्ध शिक्षाएं भारत की G-20 की अध्यक्षता के आदर्श वाक्य **'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'** के अनुरूप है।
- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच धार्मिक संबंध मजबूत भावनाओं को जागृत करता है और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले दोनों देशों के लोगों के बीच अपार सद्भावना पैदा करता है।
  - इस पैदल यात्रा की मेजबानी कोरियाई बौद्ध धर्म के जोगे ऑर्डर द्वारा की जा रही है।
  - पैदल यात्रा वाराणसी के सारनाथ से शुरू होगी और नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी।
- मेगा बौद्ध तीर्थयात्रा साझी बौद्ध विरासत के लिए एक उपयुक्त सम्मान है। यह लोगों के बीच संपर्क को और गहरा करने में काफी मददगार साबित होगी।

**तीर्थयात्रियों में भिक्षु शामिल होंगे, जो:**

1. आठ प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थलों को नमन करेंगे,

2. भारतीय बौद्ध धर्म और संस्कृति से अवगत होंगे, और धार्मिक नेताओं की द्विपक्षीय बैठक होगी और

3. विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा और जीवन की गरिमा के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित करेंगे।

## 3. युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया:

- आईजीएनसीए नई दिल्ली के सभागार में शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
  - यह एक प्रकार का राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम है।
  - जिसमें देश भर के हजारों युवा हिस्सा लेंगे। जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर देश को देखने, समझने और जानने का प्रयास करेंगे।
  - इस युवा संगम में 30 प्रतिशत पूर्वोत्तर के युवाओं की भागीदारी रहेगी।
  - "युवा संगम" कार्यक्रम 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की प्रेरणा है।

- यह कार्यक्रम पर्यटन, परम्परा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परसपर संपर्क की भावना से किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम में ना सिर्फ स्कूल और कॉलेज-यूनिवर्सिटी के छात्र हिस्सा लेंगे, बल्कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के युवा भी हिस्सा ले सकते हैं।
- इसके पंजीकरण हेतु आज से पोर्टल शुरू हो गया है।
- इस युवा संगम में 20,000 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। पहले चरण में देश के 14 विश्वविद्यालयों को इस यात्रा के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- यह कार्यक्रम हमारे पूर्वोत्तर के युवाओं को भी एक नई प्रेरणा देगा।
  - आजादी के अमृत महोत्सव में शिक्षा मंत्रालय की यह बहुत सराहनीय पहल है।
  - इस युवा संगम में गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय,पर्यटन मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय और डोनर मंत्रालय मिलकर काम करेंगे।
  - इसलिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की सम्पूर्ण सरकार दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
  - इतना ही नहीं इस अभियान में देश के सभी विभाग, सभी मंत्रालय के साथ-साथ सभी राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी।

## 4. G-20 के तहत पर्यटन कार्यसमूह की पहली बैठक गुजरात के कच्छ के रण में शुरू होगी:

- गुजरात में कच्छ के रण की लुभावनी सफेद रेत की पृष्ठभूमि में, G-20 देशों के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक 7-9 फरवरी 2023 के दौरान आयोजित की जायेगी।
- बैठक में G-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
- भारत की G-20 अध्यक्षता के अवसर पर, पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बनाई है, जिनमें न केवल सरकारी स्तर के हितधारक, बल्कि यात्रा-कारोबार और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
  - मंत्रालय अप्रैल/मई 2023 में नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन (GTIS) का आयोजन करेगा।

- GTIS का उद्देश्य पर्यटन अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्टार्टअप और अन्य में निवेश के साथ-साथ भारतीय पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है।

- जून में गोवा में मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ G-20 सीईओ फोरम आयोजित किया जाएगा।
  - यह कार्यक्रम विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (WTTC) और WTTC (भारत पहल) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
  - पर्यटन मंत्रालय मई और जून, 2023 में साहसिक पर्यटन पर क्रमश: MICE वैश्विक सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो पर्यटन क्षेत्र के परिवर्तन को गति देने के लिए प्रमुख आधार स्तम्भ होंगे और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

**पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:**

- **हरित पर्यटन** "एक सतत, जिम्मेदार और लचीले पर्यटन क्षेत्र के लिए पर्यटन क्षेत्र को हरियाली से जोड़ने का कार्य है"।
- **डिजिटलीकरण** "पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करना"।
- **कौशल** "पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाना"।
- **पर्यटन** MSME "पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और गतिशीलता लाने के लिए पर्यटन MSME/स्टार्टअप/निजी क्षेत्र का पोषण"।
- **गंतव्य प्रबंधन** "SDG पर जारी किए गए समग्र दृष्टिकोण की दिशा में गंतव्यों के रणनीतिक प्रबंधन पर पुनर्विचार"।
- ग्रामीण पर्यटन में स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और समावेशी सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने की उच्च क्षमता है।

- ग्रामीण पर्यटन ग्रामीण मूल्य और गांवों के साथ-साथ उनके संबंधित परिदृश्य, ज्ञान प्रणाली, जैविक और सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और गतिविधियों (कृषि, वानिकी, पशुधन और/या मत्स्य पालन) की रक्षा करता है, जिसमें उनकी पाककला भी शामिल है।
- दूसरे फोकस क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों में समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं, जो दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में ज्ञानपूर्ण खोज प्रदान करती हैं।
- पर्यटन को पुरातात्विक स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसी गंतव्य की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और स्थानीय समुदायों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

- विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल इस साल 31 जनवरी को शुरू की गई थी और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी कई बड़ी योजनाएं और गतिविधियां हैं।
- इस वर्ष एक लाख से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भारत का दौरा करेंगे और वे स्मारकों और त्योहारों सहित भारत की समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता को देखने पाएंगे।